Result Mitra
दैनिक जागरण
The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE
दैनिक भास्कर
THE HINDU
जनसत्ता
Daily
CURRENT
AFFAIRS
IAS/PCS
अब होगी करंट अफेयर्स की राह आसान
04 April 2025

भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

Result Mitra

भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

संदर्भ

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से मतों की गिनती के साथ वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों के 100% सत्यापन की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) को 45 दिनों के लिए 'सील एवं सुरक्षित' करने का निर्देश दिया है।

Result Mitra

भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

क्या है सिंबल लोडिंग यूनिट (SLU)?

• मतदान केंद्र पर ईवीएम में तीन यूनिट्स होती हैं - कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी प्रिंटर। इस प्रक्रिया में एक चौथा उपकरण भी शामिल होता है, जिसे सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) कहते हैं।

Result Mitra

भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

• एसएलयू लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर से जुड़ा एक उपकरण होता है। जहां से उम्मीदवारों के नाम, सीरियल नंबर और प्रतीकों वाली बिटमैप फाइल को लोड करने के लिए एक सिंबल लोडिंग एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है।

• फिर उस फाइल को पेपर ऑडिट मशीन पर ट्रांसफर करने के लिए एसएलयू को वीवीपीएटी से जोड़ा जाता है। यह जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में किया जाता है।

Result Mitra

भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

प्रतीकों को लोड करने के बाद SLU

• बहु-चरणीय चुनावों में एक चरण का मतदान संपन्न होने पर अन्य चरणों के लिए VVPAT पर प्रतीकों को लोड करने के लिए SLU का पुन: उपयोग किया जाता है।

Result Mitra

भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

• SLU केवल EVM का निर्माण करने वाली कंपनियों- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) के इंजीनियरों को ही जारी किया जाता है, ताकि बाद के चरणों के लिए VVPAT पर सिंबल को लोड करने के लिए उनका उपयोग किया जा सके।

Result Mitra

भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

SLUs के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देश

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है कि किसी सीट के लिए सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद SLU को सील कर दिया जाना चाहिए और संग्रहीत किया जाना चाहिए।
- इसे परिणाम घोषित होने के बाद 45 दिनों की अवधि तक संग्रहीत किया जाना चाहिए, ताकि चुनाव याचिका के मामले में इसे EVM की तरह खोला जा सके और जाँच की जा सके।

Result Mitra

भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

- इसका प्रभावी अर्थ यह है कि किसी सीट के लिए VVPAT पर प्रतीकों को लोड करने के लिए उपयोग किया जाने वाला SLU अब अन्य सीटों के लिए पुन: उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- एक अभूतपूर्व कदम में, सर्वोच्च न्यायालय ने उम्मीदवारों को EVM सॉफ्टवेयर के सत्यापन की मांग करने की अनुमति दी है।

Result Mitra

भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

- इसका प्रभावी अर्थ यह है कि परिणाम के संबंध में किसी भी संदेह के मामले में उम्मीदवार ECI अधिकारियों के बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं VVPAT में छेड़छाड़ के लिए केवल एक बार प्रोग्राम योग्य मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जाँच के लिए कह सकता है।
- इस सत्यापन में इन तीन घटकों के प्रयुक्त मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर का निरीक्षण करना शामिल है।

Result Mitra

भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

• EVM निर्माताओं के इंजीनियर प्रति विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र के विधान सभा क्षेत्र में 5% EVM की जाँच करेंगे। उम्मीदवारों को परिणाम की घोषणा के 7 दिनों के भीतर एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना होगा और प्रक्रिया का खर्च वहन करना होगा।

Result Mitra

भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

• हालाँकि, सत्यापन मांगने का यह अधिकार उन उम्मीदवारों तक ही सीमित है जो दूसरे या तीसरे स्थान पर आते हैं। विनिर्माण कंपनियों के इंजीनियर मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की प्रामाणिकता और अक्षुण्णता को प्रमाणित करेंगे।

• यदि सत्यापन के बाद माइक्रोकंट्रोलर के साथ छेड़छाड़ पाई जाती है तो अभ्यर्थी को सत्यापन का खर्च वापस कर दिया जाएगा।

Result Mitra

भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

ई.वी.एम. के बारे में

• सर्वप्रथम वर्ष 1982 में केरल के परूर विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का प्रयोग किया गया था। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चुनावों के दौरान मतदाताओं के मत संग्रहण के लिए उपयुक्त प्रणाली की स्थापना करता है।

Result Mitra

भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

- इसका सुझाव सर्वप्रथम वर्ष 1977 में मुख्य चुनाव आयुक्त एस.एल. शकधर की ओर से आया था।
- परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL), हैदराबाद नामक एक सार्वजनिक उपक्रम ने वर्ष 1979 में इस मशीन का एक प्रोटोटाइप विकसित किया।
- भारत निर्मित ई.वी.एम. को भूटान, नेपाल एवं नामीबिया जैसे देशों द्वारा आयात भी किया गया है।

Result Mitra

भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

ई.वी.एम. के उपयोग की शुरुआत

- सभी दलों की व्यापक सहमति के बाद वर्ष 1980 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने EVM के उपयोग के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्देश जारी किए।

Result Mitra

भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

- दिसंबर 1988 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके एक नई धारा (61A) शामिल की गई जो चुनाव आयोग को EVM का उपयोग करने का अधिकार देती है।
- यह संशोधन 15 मार्च, 1989 को लागू हुआ।

Result Mitra

भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

- भारत सरकार ने जनवरी 1990 में एक चुनाव सुधार समिति की स्थापना की जिसने जिसने मशीन की तकनीकी मूल्यांकन की सिफारिश की।
  - तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के एस. संपत की अध्यक्षता में किया गया था।
  - प्रारंभिक परीक्षणों से पता चला कि EVM से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी।

Result Mitra

भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

- वर्ष 2013 में उन्नत संस्करण के माध्यम से नोटा का विकल्प EVM में शामिल किया गया।
- वर्ष 2019 के आम चुनाव में पहली बार EVM को 100% VVPAT मशीन के साथ प्रयोग किया गया।

Result Mitra

भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

ई.वी.एम. अपनाने के कारण

- भारतीय मतदाताओं की अत्यधिक संख्या
- चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायक
- बूथ कैप्चरिंग की समस्या से निपटना
- ई.वी.एम को अपनाने को लेकर आम सहमति
- मतगणना में तेज़ी

Result Mitra

भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

अन्य देशों की स्थिति

• जिस समय EVM ने भारत में लोकप्रियता हासिल की उसी दौरान विश्व के विभिन्न देश, जैसे- इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड एवं अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।

• मार्च 2009 में जर्मन सर्वोच्च न्यायालय ने EVM के माध्यम से मतदान को असंवैधानिक बताया।

UPSC Mains GS Paper 1

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1982 में केरल के एक विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का प्रयोग किया गया था।

2. भारतीय निर्वाचन आयोग ने ईवीएम के उपयोग के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्देश सभी दलों की व्यापक सहमति के बाद वर्ष 1980 में जारी किए थे।

3. वर्ष 2019 के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम को 100% वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीन के साथ प्रयोग किया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

वोट फ्रॉम होम सुविधा

Result Mitra

वोट फ्रॉम होम सुविधा

संदर्भ

समावेशी निर्वाचन को बढ़ावा देने के क्रम में भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India : ECI) ने 'वोट फ्रॉम होम' सुविधा की शुरुआत की है।

Result Mitra

वोट फ्रॉम होम सुविधा

नवीनतम पहल

- ई.सी.आई. ने लोक सभा चुनाव के इतिहास में पहली बार विकलांग व्यक्तियों एवं 85 वर्ष व उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'वोट फ्रॉम होम' सुविधा का विस्तार किया है।
- इससे 85 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और 88.4 लाख विकलांग व्यक्तियों को डाक मतपत्रों के माध्यम से वोट डालने की अनुमति मिलेगी।

Result Mitra

वोट फ्रॉम होम सुविधा

किसको मिलेगा वोट फ्रॉम होम सुविधा का लाभ

- 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक
- 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति
- चुनावी गतिविधियों का प्रसारण करने वाले मीडियाकर्मी
- आवश्यक सेवाओं के कर्मचारी

Result Mitra

वोट फ्रॉम होम सुविधा

- सेवा मतदाता
  - अपने गृह नगर से दूर तैनात सशस्त्र बलों के कर्मी
  - घर से दूर तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मी
  - चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मी

Result Mitra

वोट फ्रॉम होम सुविधा

UPSC Mains GS Paper 2

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 'वोट फ्रॉम होम' सुविधा का लाभ केवल 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ही मिलेगा।

2. इस सुविधा के तहत पात्र मतदाता डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे।

3. भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोक सभा चुनाव के इतिहास में पहली बार इस सुविधा का विस्तार किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि

Result Mitra

बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि

संदर्भ

हाल के वर्षों में बच्चों में कैंसर की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। लोगों एवं प्राथमिक देखभाल चिकित्सकों में बाल्यावस्था कैंसर के बारे में जागरूकता में वृद्धि से ऐसे मामलों की जानकारी सामने आ रही है।

Result Mitra

बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि

बाल्यावस्था कैंसर में वृद्धि के प्रमुख कारण

नैदानिक चिकित्सा में प्रगति

बेहतर स्क्रीनिंग विधियों एवं नैदानिक उपकरणों से ट्यूमर की शीघ्र पहचान संभव हो सकी है। पूर्व में अज्ञात मामलों का अब निदान किया जा रहा है, जिससे बचपन में कैंसर के मामले अब सामने आ रहे हैं जो इसकी वृद्धि का कारक है।

Result Mitra

बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि

जीवनशैली का प्रभाव

आहार शैली में बदलाव, शारीरिक गतिविधियों एवं आउटडोर गेम में कमी, क्रियाशील आदतों में कमी और लंबे समय तक स्क्रीन पर समय बिताने जैसी बदलती जीवनशैली बच्चों के समग्र स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। अस्वास्थ्यकर जीवनशैली कैंसर के विकास का एक कारक है।

Result Mitra

बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि

पर्यावरणीय कारक

वर्तमान में बच्चे तेज़ी से अपने परिवेश में मौजूद कैंसरकारी तत्वों के संपर्क में आ रहे हैं। इनमें मुख्यत: प्रदूषित तत्व, औद्योगिक एवं कृषि प्रक्रियाओं से निकलने वाले रसायन शामिल हैं। इस तरह के जोखिम कैंसर के विकास के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं।

Result Mitra

बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि

वायरल संक्रमण एवं कमज़ोर प्रतिरक्षा

कुछ वायरल संक्रमण आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं जिससे कैंसर विकास का खतरा बढ़ जाता है। उपलब्ध टीकाकरण एवं एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली इन संक्रमणों पर नियंत्रण पा सकती है।

Result Mitra

बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि

सामाजिक एवं आर्थिक कारक

• सामाजिक-आर्थिक असमानताएं बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, त्वरित निदान एवं उपचार विकल्पों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं।

• वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे प्राय: उन बाधाओं का सामना करते हैं जो समय पर निदान एवं उचित चिकित्सा देखभाल में बाधा डालती हैं जिससे बाल्यावस्था कैंसर से जुड़ी चुनौतियां बढ़ जाती हैं।

Result Mitra

बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि

बाल्यावस्था कैंसर रोकथाम के उपाय

बाल कैंसर प्रबंधन में प्रगति

बाल चिकित्सा के क्षेत्र में ऑन्कोलॉजी की प्रगति से बाल्यावस्था के कैंसर से जीवित रहने की दर में सुधार हुआ है। कैंसर से पीड़ित लगभग 80% बच्चे शीघ्र निदान एवं उचित उपचार से ठीक हो सकते हैं।

Result Mitra

बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि

उन्नत जन-जागरूकता अभियान

जन-जागरूकता के माध्यम से माता-पिता एवं देखभाल करने वालों को कैंसर के शीघ्र पता लगाने के महत्व के बारे में शिक्षित करने और फल व सब्जीयुक्त संतुलित आहार लेने, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से परहेज करने, आउटडोर गेम्स, शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने जैसे स्वस्थ जीवनशैली विकल्पों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है।

Result Mitra

बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि

कैंसरकारी तत्वों से बचाव

कैंसरकारी कारकों से बचाव के उद्देश्य से मजबूत पर्यावरणीय नियम एवं नीतियाँ पर्यावरणीय कारकों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक हैं।

Result Mitra

बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि

अनुसंधान एवं विकास पर बल

बाल्यावस्था कैंसर में योगदान देने वाले आनुवंशिक, पर्यावरणीय व जीवनशैली आधारित कारकों की जटिल परस्पर क्रिया को जानने के लिए अनुसंधान में निवेश आवश्यक है।

Result Mitra

बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि

उच्च जोखिम वाली आबादी की पहचान करना

उच्च जोखिम वाली आबादी की पहचान करने और लक्षित हस्तक्षेपों को लागू करने से कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए सकारात्मक परिणाम बढ़ सकते हैं। इससे बीमारी के समग्र बोझ को कम करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

UPSC Mains GS Paper 2

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. समकालीन भारतीय प्रशासनिक प्रणाली की कई विशेषताएँ ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणालियों से विरासत में मिली हैं।
2. स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों में भारत ने मुख्य रूप से पूर्ण आत्मनिर्भरता और आयात प्रतिस्थापन पर आधारित कल्याणकारी आर्थिक नीतियाँ अपनाईं।
3. 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद, अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने भारतीय प्रशासन के तरीकों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

Result Mitra

भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

संदर्भ

आयुर्वेद उत्पाद बनाने वाली कंपनी पतंजलि को भ्रामक विज्ञापनों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की फटकार का सामना करना पड़ा है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य मंत्रालय ने भी 10 अप्रैल, 2024 के एक आदेश में कहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने पोर्टल पर सभी पेय पदार्थों को 'स्वास्थ्यवर्धक पेय' श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। यह आदेश राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की एक वर्ष तक चली जांच के बाद आया है। NCPCR ने माल्टेड व 78 वर्ष पुराने बोर्नविटा ब्रांड को लेकर यह जांच की थी।

Result Mitra

भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने भी 2 अप्रैल, 2024 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से अनुरोध किया था कि वे डेयरी, अनाज या माल्ट आधारित पेय पदार्थों को 'स्वास्थ्यवर्धक पेय' या 'ऊर्जावर्धक पेय' के रूप में वर्गीकृत न करें। ऐसा वर्गीकरण ग्राहकों को भ्रमित करता है।

Result Mitra

भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

भ्रामक विज्ञापन से तात्पर्य

• उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार, भ्रामक विज्ञापन को ऐसे विज्ञापन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी उत्पाद या सेवा का गलत वर्णन करता है, झूठी गारंटी देता है, उसकी प्रकृति या गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ताओं को गुमराह करने की संभावना रखता है, अनुचित व्यापार प्रथा का प्रतिनिधित्व करता है या जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छुपाता है।

Result Mitra

भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

- विज्ञापन वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रचार का माध्यम माना जाता है किंतु, जब विज्ञापनकर्ता जानबूझकर मिथ्या प्रचार करते हैं और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, तब यह आपत्तिजनक हो जाता है।

Result Mitra

भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

• यदि कोई उत्पादक अथवा विज्ञापनकर्ता किसी उत्पाद के बारे में कोई दावा करता है, तो उसके उसे सिद्ध भी करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो इसे भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा तथा देश के विभिन्न कानूनों के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

Result Mitra

भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

भ्रामक विज्ञापनों के दुष्प्रभाव

- उपभोक्ताओं के सूचना, सुरक्षा एवं चयन के मौलिक अधिकारों का हनन
- भ्रामक विज्ञापनों के प्रभाव में कई बार स्वास्थ्य व जीवन के लिए घातक वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग
- शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षति की संभावना
- विज्ञापनों के दृश्यों का बच्चों के मन व मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव

विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले हिंसक व उत्तेजक दृश्यों की नकल कई बार बच्चों द्वारा किए जाने लगती है।

Result Mitra

भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

भ्रामक विज्ञापनों पर निगरानी की आवश्यकता

- कई ब्रांड्स अपने उत्पादों के पैकेट पर 'स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद' लिख देते हैं, जबकि NCPCR ने पाया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत 'स्वास्थ्यवर्धक पेय' की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है।

Result Mitra

भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

- भारत में बच्चों को लक्षित करने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों के विज्ञापनों को लेकर ज्यादा चिंता है। देशी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां रणनीति के तहत तथ्यों से छेड़छाड़ करती हैं और अपने उत्पादों को स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद के लेबलिंग के साथ बाजार में बेचती हैं।
  - उदाहरण के लिए बोर्नविटा ने 'माल्टोडेक्सट्रिन' एवं 'लिक्विड ग्लूकोज' जैसे लेबल का इस्तेमाल करके चीनी की सीमा को कम करके दिखाया था।

Result Mitra

भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

- FSSAI के लेबलिंग एवं डिस्प्ले नियम, 2020 के अनुसार, इन्हें भी चीनी के लेबल के अंतर्गत ही दिखाया जाना चाहिए।
- इसी प्रकार पतंजलि ने 'एलोपैथी द्वारा फैलाई गई गलतफहमियां' नामक शीर्षक से समाचार-पत्र में अपना विज्ञापन दिया था, जिसके कारण कंपनी को सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगनी पड़ी है।

Result Mitra

भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

- साथ ही, वैकल्पिक दवाओं एवं पैकेट बंद भोजन का बाजार (खासकर बच्चों पर केंद्रित) तेजी से बढ़ रहा है इसलिए उपभोक्ता कल्याण के लिए अधिक मजबूत निगरानी संस्था की जरूरत है।

Result Mitra

भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

सरकार द्वारा बनाए गए प्रमुख कानून

- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
- खाद्य अपमिश्रण उन्मूलन अधिनियम, 1955
- केबल टेलीविजन नेटवर्क नियंत्रण अधिनियम, 1995
- वस्तु बिक्री अधिनियम, 1930

UPSC Mains GS Paper 2

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार, भ्रामक विज्ञापन वह है जो किसी उत्पाद या सेवा का गलत वर्णन करता है या झूठी गारंटी देता है।

2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार, 'स्वास्थ्यवर्धक पेय' की एक आधिकारिक परिभाषा मौजूद है जिसका उपयोग खाद्य उत्पादों के विपणन में किया जा सकता है।

3. भ्रामक विज्ञापनों का उपभोक्ताओं के सूचना, सुरक्षा एवं चयन के मौलिक अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

Thank you !

Result Mitra